दृष्टि
The Vision

करेंट अफेयर्स हरियाणा

अगस्त (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

हरियाणा **5**

- 'पॉवर टैरिफ सब्सिडी' योजना ('Power Tariff Subsidy' Scheme) 5
- हर हित स्टोर योजना (Har Hith Store Yojana) 5
- भूमि बैंक बनाने के लिये नीति 6
- हरियाणा में कर्मचारियों के लिये मानव संसाधन विकास विभाग 6
- नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास 7
- हरियाणा में 'GST मॉडल-2' लॉन्च 7
- रंजीता शर्मा : 'स्वार्ड ऑफ ऑनर अवॉर्ड' पाने वाली देश की पहली महिला 8
- हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी देश की पहली पैसेंजर ट्रेन 8
- मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ (Soil Testing Laboratories) 8
- हरियाणा में 15 साल पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध 9

नोट :

- हरियाणा सरकार ने ओलंपिक पदक विजेताओं, प्रतिभागियों को सम्मानित किया 9
- हरियाणा के दो स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि की रामसर सूची में 10
- पी.के. अग्रवाल (Prashanta Kumar Agrawal) 10
- 'परिवर्तन' परियोजना 11
- 'अपशिष्ट से ऊर्जा' संयंत्र 11
- 'गोरख धंधा' शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध 11
- हरियाणा के हर ज़िला मुख्यालय में बनेगा आधुनिक पंचायत भवन 12
- प्रतिस्मृति: एलुमनी रीयूनियन 2021 12
- जल प्रबंधन के लिये हरियाणा को मिला पुरस्कार 12
- भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 13
- ई-भूमि पोर्टल 13
- सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में जीता गोल्ड मेडल 14

नोट :

दृष्टि
The Vision

नोट :

हरियाणा

'पॉवर टैरिफ सब्सिडी' योजना ('Power Tariff Subsidy' Scheme)

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (Micro & Small Enterprises) को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिये 'पॉवर टैरिफ सब्सिडी' योजना अधिसूचित की है।
  - यह योजना 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी मानी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा उद्यम एवं रोज़गार नीति 2020 के तहत 'पॉवर टैरिफ सब्सिडी' योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत छोटे उद्योगों को ` 2 प्रति यूनिट सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य के 'डी' श्रेणी के विकास खंडों में 40 किलोवाट और 'सी' श्रेणी के विकास खंडों में 30 किलोवाट या उससे कम के कनेक्टेड लोड वाले सभी मौजूदा और नए सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक उद्यमों को बिजली टैरिफ सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
- इसका लाभ उठाने के लिये किसी प्रकार का आवेदन नहीं करना होगा, हरियाणा बिजली वितरण निगम बिलों में से सब्सिडी राशि काटकर योजना का लाभ प्रदान करेंगे।

हर हित स्टोर योजना (Har Hith Store Yojana)

चर्चा में क्यों ?

- 2 अगस्त, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिये पंचकूला में 'हर हित स्टोर योजना' का शुभारंभ एवं इसके पोर्टल को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत प्रदेश में पहले चरण में 2000 स्टोर (ग्रामीण क्षेत्र में 1500 एवं शहरी क्षेत्र में 500) और दूसरे चरण में 5,000 स्टोर स्थापित किये जाएंगे।
- इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक ज़रूरत के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुँच सुनिश्चित होगी।
- इस योजना के तहत हरियाणा सरकार युवा फ्रेंचाइजी के साथ-साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एमएसएमई), सरकारी सहकारिता संस्थाओं, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के व्यापार को बढ़ाने के लिये मंच प्रदान करेगी।
- राज्य में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोज़गार न रहें, इस उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हरियाणा को 'बेरोज़गार मुक्त-रोज़गार युक्त' (Berojgar Mukt, Rozgar Yukt) बनाना है।
- हर हित स्टोर योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार एक स्टोर का अवलोकन भी किया।
- हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3000 या अधिक आबादी वाले गाँव में 200 वर्ग फुट पर एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा। नगरपालिका समिति, परिषद में ऐसे वार्ड, समूह जिनकी संचयी जनसंख्या 10,000 हो, वहाँ पर एक-एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि परिवार पहचान-पत्र के तहत जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय 1 लाख 80 हज़ार रुपए से कम है, उन परिवारों के युवाओं को भी इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
- इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की है कि यदि इन परिवारों के युवा हर हित स्टोर खोलने के लिये रुचि दिखाते हैं तो राज्य सरकार युवाओं को हर माह न्यूनतम 15 हज़ार रुपए की आय सुनिश्चितता की गारंटी भी देगी।
- हर हित स्टोर की बिक्री प्रावधानों के अनुसार, जो फ्रैंचाइजी पार्टनर 1,50,000 रुपए की ब्रिकी करेगा, उसे 10 प्रतिशत के हिसाब से 15 हज़ार रुपए की आय होगी।
- यदि पीपीपी में न्यूनतम आय परिवारों के युवा शुरुआती 6 महीनों में न्यूनतम 15 हज़ार रुपए की आय अर्जित करने में असमर्थ रहते हैं तो राज्य सरकार 6 महीने तक उन्हें न्यूनतम आय सुनिश्चित करने की गारंटी देगी।
- यदि युवा 12 हज़ार रुपए कमा सका तो सरकार द्वारा उसे 3 हज़ार रुपए, यदि 12 हज़ार रुपए से ऊपर, लेकिन 15 हज़ार रुपए से नीचे आय अर्जित कर सका तो सरकार द्वारा उसे 2,000 रुपए की राशि देकर उसकी न्यूनतम 15 हज़ार रुपए की आय सुनिश्चित करेगी।

भूमि बैंक बनाने के लिये नीति

चर्चा में क्यों ?

- 5 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई, मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण की कठिन प्रक्रिया से बचते हुए प्रदेश में भूमि बैंक बनाने की सरकार की नीति को मंजूरी दी गयी।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति को 'बोर्डों एवं निगमों सहित सरकारी परियोजनाओं के लिये भूमि बैंक सृजित करने और विकास परियोजनाओं के लिये उनका निपटान नीति कहा जाएगा।
- इस नीति के लिये तीन समितियां भूमि एवं दर जाँच समिति, भूमि बैंक समिति और उच्चाधिकार प्राप्त भूमि बैंक समिति का गठन किया जाएगा।
- इस नीति के अनुसार , अब किसान सहित अन्य लोग मजबूरी में नहीं बल्कि मोलभाव कर सीधे सरकार को अपनी जमीन बेच सकेंगे। राजस्व विभाग इस भूमि बैंक को संभालेगा और जरूरत के अनुसार निगमों , बोर्डों या विभागों को हस्तांतरित करेगा।
- किसान को जमीन बेचने के लिये निदेशक भूमि अभिलेख के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके लिये उन्हें मूल्य सहित भूमि का पूरा विवरण देना होगा।
- राजस्व विभाग द्वारा अपनी परियोजनाओं के लिये नगर पालिका सीमा के भीतर और उससे दो मील की दूरी तक बनाने को इसे सरकारी विभागों को स्थानांतरित किया जा सकेगा।
- बोर्डों और निगमों सहित सभी विभाग ऐसी भूमि का पता लगाने का प्रयास करेंगे, जो 'शामलात देह में हों। इस जमीन का इस्तेमाल सरकारी कार्यालय स्थापित करने में हो सकेगा।
- हरियाणा नगर पालिका अधिनियम , 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम , 1994 के तहत अचल संपत्ति को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रावधान है। ऐसे में ऐसी जमीन की भी तलाश की जाएगी।

हरियाणा में कर्मचारियों के लिये मानव संसाधन विकास विभाग

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा में 'मानव संसाधन विकास विभाग' (Human Resource Development Department) गठित करने का निर्णय लिया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में पहली बार 'मानव संसाधन विकास विभाग' गठित किया जा रहा है, जो कर्मचारियों की भर्ती से लेकर तबादलों, प्रतिनियुक्ति, सेवा नियमों में बदलाव और भ्रष्टाचार के मामलों सहित कर्मचारियों से जुड़े सभी मामले देखेगा।
- मानव संसाधन विकास विभाग हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) के साथ ही ग्रुप A, B, C और D के सभी अफसर-कर्मचारियों पर एकीकृत प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करेगा।

नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास

चर्चा में क्यों ?

- 7 अगस्त, 2021 को हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है।

प्रमुख बिंदु

- नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर तालिका में पहला स्थान हासिल कर देश को टोक्यो ओलंपिक का पहला और व्यक्तिगत श्रेणी में ओलंपिक का दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया है।
- नीरज हरियाणा के पानीपत ज़िले के 'खंडरा' गाँव के निवासी हैं।
- वर्ष 2016 से नीरज भारतीय सेना में कार्यरत हैं और वर्तमान में राजपूताना राइफल्स यूनिट में सूबेदार के पद पर हैं।
- नीरज चोपड़ा को वर्ष 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
- नीरज ने भारत को 10वाँ ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया है, गौरतलब है कि 8 स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी टीम ने और 1 स्वर्ण पदक निशानेबाज अभिनव बिंद्रा (पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक) द्वारा जीता गया था।
- नीरज के अब तक के अन्य खेलों में स्वर्ण पदक:
  1. 2018 जकार्ता, एशियाई खेल
  2. 2018 गोल्ड कोस्ट, राष्ट्रमंडल खेल
  3. 2017 भुवनेश्वर, एशियाई चैंपियनशिप
  4. 2016 गुवाहाटी/शिलांग, दक्षिण एशियाई खेल

हरियाणा में 'GST मॉडल-2' लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में जीएसटी के कार्यान्वयन हेतु जीएसटी 'मॉडल-2' की नई प्रणाली का उद्घाटन किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस पहल से प्रदेश में कर संचय बढ़ने के साथ-साथ व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने में भी आसानी होगी।
- राज्य के जीएसटी 'मॉडल-1' को बदलकर 'मॉडल-2' की नई प्रणाली में परिवर्तित करने से विभाग का कामकाज पहले की तुलना में अधिक आधुनिक, तेज और बेहतर डेटा की गुणवत्ता वाला बन गया है।
- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस अवसर पर आबकारी एवं कराधान विभाग को आधुनिक तकनीक से अपडेट रखने की भी बात की।
- गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा ने 4 मई, 2017 को 'हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017' पारित किया था, जिसे 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया।

नोट :

रंजीता शर्मा : 'स्वार्ड ऑफ ऑनर अवॉर्ड' पाने वाली देश की पहली महिला

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के आरआर-72 बैच की अधिकारी 'रंजीता शर्मा' आईपीएस एसोसिएशन के 'स्वार्ड ऑफ ऑनर अवॉर्ड' को प्राप्त करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी हैं।

प्रमुख बिंदु

- 'स्वार्ड ऑफ ऑनर अवॉर्ड' प्रशिक्षण के दौरान 'फील्ड ट्रेनिंग' के आधार पर दिया जाता है।
- ट्रेनिंग के दौरान रंजीता शर्मा ने वितरित की गई कुल 50 ट्राफियों में से आठ ट्राफियाँ जीतने की उपलब्धि हासिल की है।
- रंजीता शर्मा रेवाड़ी ज़िले के गाँव 'डहीना' की निवासी हैं और ये वर्ष 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं।

हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी देश की पहली पैसेंजर ट्रेन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय रेलवे ने हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा में हाइड्रोजन ईंधन सेल के जरिये ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन' के अंतर्गत हरियाणा में 'सोनीपत-जींद' के 89 किलोमीटर रेलवे मार्ग पर देश में पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी।
- भारत में डीएमयू (डीजल मल्टिपल यूनिट) में इसके इस्तेमाल का फैसला लिया गया है। शुरुआती दौर में दो डीएमयू रेक में बदलाव करके हाइड्रोजन ईंधन सेल लगाए जाएंगे।
- गौरतलब है कि 'पेरिस जलवायु समझौता 2015' के अंतर्गत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने तथा रेलवे द्वारा 'जीरो कार्बन उत्सर्जन मिशन' के अंतर्गत 2030 तक लक्ष्य प्राप्ति हेतु यह निर्णय लिया गया है।
- जर्मनी और पोलैंड के बाद भारत विश्व का तीसरा देश होगा, जहाँ 'हाइड्रोजन ईंधन' आधारित ट्रेन का प्रयोग शुरू किया जा रहा है।

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ (Soil Testing Laboratories)

चर्चा में क्यों ?

- 12 अगस्त, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में ब्लॉकस्तर पर स्थापित 40 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार के 'हर खेत स्वस्थ खेत' के तहत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं।
- इसका उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य के आधार पर फसल की बुवाई करने हेतु जानकारी उपलब्ध कराना है।
- पहले चरण में इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से इस वर्ष 25 लाख एकड़ भूमि का मृदा परीक्षण किया जाएगा, जबकि अगले तीन साल में हरियाणा की पूरी 75 लाख एकड़ कृषि भूमि का मिट्टी परीक्षण किया जाएगा।
- गौरतलब है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान पंचकूला और करनाल स्थित दो मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला (एनएबीएल) के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही हरियाणा भारत का पहला राज्य होगा, जिसके पास भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता होगी।

नोट :

हरियाणा में 15 साल पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के गैर-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी ज़िलों में राज्य कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज परमिट वाले 15 साल पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न प्रकार के परिवहन वाहनों के संचालन के लिये आयु जोड़ने हेतु हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन करने के लिये मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है।
- हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार, राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और गैर-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दो अलग-अलग श्रेणियाँ बनाई गई हैं। वर्तमान में एनसीआर क्षेत्र में हरियाणा के 13 ज़िले शामिल हैं।
- नियमों में कहा गया है कि एनसीआर क्षेत्र और गैर-एनसीआर क्षेत्र, दोनों में संचालित होने वाले वाहनों की अधिकतम आयु पर्यटक परमिट (मोटर कैब) के लिये 9 वर्ष होगी। मोटर कैब के अलावा अन्य टूरिस्ट परमिट के लिये एनसीआर क्षेत्र और गैर-एनसीआर क्षेत्र में आयु सीमा आठ वर्ष होगी।
- इसी प्रकार राज्य कैरिज, अनुबंध कैरिज, माल ढुलाई सहित अन्य सभी परमिटों के लिये सीएनजी/इलेक्ट्रिक/स्वच्छ ईंधन वाहनों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष होगी, जबकि एनसीआर क्षेत्र में डीज़ल वाहनों के लिये यह 10 वर्ष होगी। गैर-एनसीआर क्षेत्र के लिये दोनों श्रेणियों के वाहनों हेतु आयु सीमा 15 वर्ष होगी।
- गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2015 के आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल कारों का जीवन चक्र 15 साल, जबकि डीज़ल कारों का 10 साल होता है। हरियाणा सरकार ने 2016 में भी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिये एनसीआर ज़िलों में सड़कों से 15 वर्षीय पेट्रोल और 10 वर्षीय डीज़ल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये थे।

हरियाणा सरकार ने ओलंपिक पदक विजेताओं, प्रतिभागियों को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों ?

- 13 अगस्त, 2021 को हरियाणा सरकार ने पंचकूला में आयोजित एक सम्मान समारोह में राज्य के टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार और नौकरी-पत्र के साथ सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और राज्य मंत्रिपरिषद के साथ टोक्यो ओलंपिक में राज्य के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया।
- इस अवसर पर राज्यपाल ने खिलाड़ियों को राज्य की खेल नीति के अनुसार दिये जाने वाले जॉब ऑफर लेटर के साथ 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के चेक वितरित किये।
- हरियाणा के रजत पदक विजेता पहलवान रवि कुमार दहिया, कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार, महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी और अन्य ओलंपिक प्रतिभागियों ने समारोह में भाग लिया। राज्य के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा स्वास्थ्य कारणों से समारोह में शामिल नहीं हुए।
- गौरतलब है कि इस बार भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ सात ओलंपिक पदकों में से तीन व्यक्तिगत पदक विजेता और भारत की पुरुष हॉकी टीम में दो खिलाड़ी हरियाणा के थे।
- हरियाणा के दो हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार और सुमित कुमार 41 साल के लंबे इंतज़ार के बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। वहीं हरियाणा की नौ महिलाएँ भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा थीं, जिन्होंने ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहते हुए शानदार प्रदर्शन किया।

नोट :

- ध्यातब्य है कि राज्य सरकार द्वारा उन सभी पैरालंपिक पदक विजेताओं और पैरा खिलाड़ियों को भी सामान्य खिलाड़ियों के समान नकद पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है, जिन्होंने ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है।

हरियाणा के दो स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि की रामसर सूची में

चर्चा में क्यों ?

- 14 अगस्त, 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, रामसर कन्वेंशन के तहत हरियाणा में दो स्थलों भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य तथा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा के इन दो स्थलों के साथ ही गुजरात के 2 स्थलों- थोल झील वन्यजीव अभयारण्य और वधवाना को भी आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे देश में ऐसे स्थलों की संख्या अब 46 हो गई है।
- ऐसा पहली बार है कि जब हरियाणा से दो स्थलों- गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर से भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को रामसर सूची में डाला गया है।
- भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य मानवनिर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। यह हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। वर्ष भर पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियाँ इस अभयारण्य का उपयोग विश्रामस्थल के रूप में करती हैं। यह स्थल मिस्र के गिद्ध, स्टेपी ईगल, पलास की फिश ईगल और ब्लैक-बेलिड टर्न सहित विश्व स्तर पर 10 से अधिक विलुप्तप्राय प्रजातियों के उपयुक्त है।
- सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान उसके मूल पक्षियों, शीतकालीन प्रवासियों और स्थानीय प्रवासी जलपक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों के लिये उनके जीवन चक्र के महत्त्वपूर्ण चरणों में अनुकूल है। इनमें से 10 से अधिक प्रजातियाँ वैश्विक स्तर पर विलुप्तप्राय श्रेणी में आती हैं।
- गौरतलब है कि रामसर संधि आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत् उपयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका नाम कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहाँ 2 फरवरी, 1971 को संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- रामसर सूची का उद्देश्य 'आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना है, जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण के लिये और उनके पारिस्थितिक तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है'।

पी.के. अग्रवाल (Prashanta Kumar Agrawal)

चर्चा में क्यों ?

- 16 अगस्त, 2021 को हरियाणा पुलिस के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक पी.के. अग्रवाल ने पंचकूला पुलिस मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अपना पदभार संभाल लिया।

प्रमुख बिंदु

- 15 अगस्त, 2021 को हरियाणा सरकार ने पी.के. अग्रवाल को पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्त किया था। उन्हें मनोज यादव के स्थान पर डीजीपी बनाया गया है।
- हरियाणा सरकार ने संघ लोग सेवा आयोग को पाँच आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा था। इसमें आईपीएस शत्रुजीत कपूर और देशराज का नाम भी शामिल था, लेकिन यूपीएससी ने दोनों को अंतिम तीन में शामिल नहीं किया था।
- संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने वरिष्ठता का पैमाना बनाते हुए नए डीजीपी की नियुक्ति के लिये तीन नामों का पैनल हरियाणा सरकार को भेजा था, जिसमें आईपीएस पी.के. अग्रवाल, रमेश चंद्र मिश्रा और मोहम्मद अकील के नाम शामिल थे।
- 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अग्रवाल मूलरूप से बिहार के रहने वाले हैं। अभी तक वह डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पर कार्यरत् थे। वे 30 जून, 2023 को सेवानिवृत्त होंगे।
- पी.के. अग्रवाल को 2004 में पुलिस मेडल और 2015 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया जा चुका है।

नोट :

'परिवर्तन' परियोजना

चर्चा में क्यों ?

- 16 अगस्त, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में 'परिवर्तन' परियोजना का उद्घाटन किया, जिसके तहत पहले चरण में 600 डीज़ल से चलने वाले तिपहिया वाहनों को ई-थ्री व्हीलर से बदला जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस पहल के तहत गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी), गुरुग्राम क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण और यातायात पुलिस के संयुक्त प्रयासों से गुरुग्राम में डीज़ल तिपहिया वाहनों के स्थान पर ई-ऑटो रिक्शा चलेंगे।
- परिवर्तन परियोजना के तहत यह अभियान गुरुग्राम से शुरू किया गया है और 5,000 ई-वाहन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना न केवल गुरुग्राम में, बल्कि हरियाणा के अन्य महानगरों में भी शुरू की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत पुराने डीज़ल ऑटो रिक्शा को ई-ऑटो रिक्शा या ई-रिक्शा में बदला जाएगा। इसके लिये एमसीजी और 'फेम इंडिया'से सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और बैंकों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था भी की जा रही है।

'अपशिष्ट से ऊर्जा' संयंत्र

चर्चा में क्यों ?

- 16 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री ने गन्नौर में स्थापित 'अपशिष्ट से ऊर्जा'संयंत्र का गुरुग्राम से डिजिटल उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- 176.87 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस 'अपशिष्ट से ऊर्जा' संयंत्र को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर तैयार किया गया है।
- इस प्लांट में सोनीपत और पानीपत ज़िले के स्थानीय निकायों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण किया जाएगा और बिजली भी पैदा की जाएगी।
- इस परियोजना से प्रतिदिन 750 टन अपशिष्ट का निपटान होगा, साथ ही इससे 8 मेगावॉट बिजली का भी उत्पादन होगा, जो ग्रिड को दी जाएगी।
- इसका रियायतग्राही जेबीएम एनवायरो है तथा परियोजना की रियायत अवधि 22 वर्ष है। इस संयंत्र से 2035 तक प्रतिदिन 750 टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा।

'गोरख धंधा' शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

- 18 अगस्त, 2021 को हरियाणा सरकार ने अनैतिक प्रथाओं का वर्णन करने के लिये आमतौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले 'गोरख धंधा' शब्द पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गोरखनाथ समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद इस संबंध में निर्णय लिया।
- गोरखनाथ समुदाय ने उनसे 'गोरख धंधा' शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था और कहा था कि यह संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करता है।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोरखनाथ संत थे और इस शब्द का किसी भी आधिकारिक भाषा, भाषण या किसी भी संदर्भ में उपयोग करने से उनके अनुयायियों की भावनाएँ आहत होती हैं, इसलिये किसी भी संदर्भ में इस शब्द के उपयोग पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हरियाणा के हर ज़िला मुख्यालय में बनेगा आधुनिक पंचायत भवन

चर्चा में क्यों ?

- 19 अगस्त, 2021 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के प्रत्येक ज़िला मुख्यालय में 'आधुनिक पंचायत भवन' बनाए जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- उपमुख्यमंत्री ने लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की।
- इस दौरान उन्होंने विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए 'भवन' के निर्माण के लिये नक्शे की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
- दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक ज़िला मुख्यालय पर 'आधुनिक पंचायत भवन' बनाया जाएगा, जिसमें ज़िला परिषद के अध्यक्ष व पार्षदों के लिये अलग-अलग कक्ष बनाए जाएंगे।

प्रतिस्मृति: एलुमनी रीयूनियन 2021

चर्चा में क्यों ?

- 19 अगस्त, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य आतिथ्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा 'प्रतिस्मृति: एलुमनी रीयूनियन 2021' कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुरुक्षेत्र पूर्व छात्र संघ (कुक्का) द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 21 से अधिक देशों से पूर्व छात्र भौतिक और ऑनलाइन रूप में शामिल हुए।
- इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व छात्र पंजीकरण पोर्टल Kukaa.ac.in, एक बहुउद्देश्यीय खेल हॉल और पूर्व छात्रों के लिये अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का भी उद्घाटन किया। साथ ही, उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिये एक जिंगल भी लॉन्च किया
- उन्होंने विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत केजी-टू-पीजी स्कीम और नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये चलाए जाने वाले जापानी भाषा के सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स, बीबीए ऑनर्स तथा एमटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी कोर्स को लॉन्च किया।
- मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (केयू) में जापानी भाषा पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिये पहले छात्र के रूप में नामांकन करेंगे।
- गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की आधारशिला भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 जनवरी, 1957 को रखी थी। समय के साथ, केयू ने एक बहु-विषयक संस्थान के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हरियाणा का पहला ए प्लस ग्रेड विश्वविद्यालय बनकर केयू ने प्रदेश और देश में गौरव हासिल किया है।

जल प्रबंधन के लिये हरियाणा को मिला पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 22 अगस्त, 2021 को हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन विभाग को केंद्रीय जल मंत्रालय के सहयोग से 'एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन' द्वारा प्लैटिनम श्रेणी में 'एनर्जी एनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल इनोवेशन इन वॉटर टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021' से सम्मानित किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान हरियाणा को यह सम्मान दिया।
- हरियाणा सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता सतबीर कादियान ने बताया कि हरियाणा को यह पुरस्कार जल प्रबंधन की उत्कृष्ट योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मिला है।
- उन्होंने कहा कि राज्य की लिफ्ट नहर प्रणाली की लगातार सराहना हो रही है और इसकी जल प्रबंधन नीतियों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है।

भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक

चर्चा में क्यों ?

- 24 अगस्त, 2021 को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021' पारित हो गया।

प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्य विधानसभा द्वारा पारित छह विधेयकों में से एक है।
- विधानसभा में पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिये भेजा जाएगा। मंज़ूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा और सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने पर लागू होगा।
- संशोधन विधेयक के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिये किसानों की सहमति लेने का काम DC (District Collector) करेंगे।
- अधिग्रहण के बाद सरकार किसी भी समय ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकती है। 48 घंटे पूर्व नोटिस देने की बाध्यता नहीं होगी।
- पुरातत्त्व स्थलों व वन भूमि को अधिग्रहण के दौरान सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाएगा।
- सरकार जिन किसानों से 200 एकड़ से कम ज़मीन खरीदेगी, उन्हें कुल कीमत के अलावा 50 फीसदी अतिरिक्त राशि का एकमुश्त भुगतान करेगी।
- गौरतलब है कि हरियाणा 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने वाला पहला राज्य नहीं है। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य पहले ही इसमें संशोधन कर चुके हैं। कुल 16 राज्यों ने अपनी सुविधानुसार इस कानून में संशोधन किये हैं।

ई-भूमि पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

- 27 अगस्त, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी (एचपीएलपीसी) की बैठक में छह ज़िलों- रेवाड़ी, नूंह, सिरसा, फरीदाबाद, सोनीपत और जींद में सात परियोजनाओं के लिये भू-मालिकों की सहमति के साथ ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से 311 एकड़ भूमि की खरीद को मंज़ूरी दी गई, जिसकी लागत लगभग 172 करोड़ रुपए है।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के सात एजेंडों को मंज़ूरी दी गई।
- इनमें रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना, नूंह ज़िले में चार लेन मेडिकल कॉलेज रोड से गुरुग्राम-अलवर रोड (एनएच 248ए) तक रिंग रोड का निर्माण, सिरसा में अतिरिक्त अनाज़ मंडी का विकास, सेंट्रल रोड फंड की अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी योजना के तहत यमुना नदी पर जसना मंझावली अट्टा गुजरान होते हुए ग्रेटर नोएडा के लिये सड़क और पुल का निर्माण शामिल हैं।

नोट :

- इसी तरह सोनीपत ज़िले में गन्नौर रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली-अंबाला सेक्शन में दो लेन आरओबी का निर्माण, सिरसा ज़िले में महाग्राम योजना के तहत चौटाला गाँव में सीवरेज सिस्टम एसटीपी का निर्माण तथा जींद में नहर आधारित जलापूर्ति योजना का निर्माण शामिल हैं।

सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में जीता गोल्ड मेडल

चर्चा में क्यों ?

- 30 अगस्त, 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में हरियाणा के सोनीपत के सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।

प्रमुख बिंदु

- पुरुषों के भालाफेंक/जैवलिन थ्रो में एफ 64 वर्ग में सुमित ने एक के बाद एक तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। पहले उन्होंने 66.95 मीटर दूर भाला फेंक कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। फिर अपनी दूसरी ही कोशिश में 68.08 मीटर के स्कोर से अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सुधारा। पाँचवीं कोशिश में उन्होंने 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
- गौरतलब है कि साल 2015 में सड़क दुर्घटना में अपना एक पैर गँवाने वाले सुमित का कोच वीरेंद्र धनखड़ ने मार्गदर्शन किया। साल 2018 में एशियन चैंपियनशिप में सुमित को 5वीं रैंक मिली थी। अगले साल 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता। इसी साल हुए नेशनल गेम्स में सुमित ने गोल्ड मेडल जीता।

दृष्टि The Vision

नोट :